(b) if so, the details thereof;

(c) whether a high level inquiry has been ordered by the Home Minister; and

(d) if so, whether the Intelligence Bureau has submitted a report?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Ministry of Home Affairs had ordered an inquiry by the Special Secretary, MHA into certain nquiries made by the police with regard to the character and antecedents of the top defence services personnel in the Army, Air Force and Navy, who were to attend the Combined Commanders' Conference, 1998. The report has since been submitted.

(d) Does not arise.

Naval base on Gujarat coast

1889. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government are considering setting-up a Naval base on Gujarat coast keeping in view its proximity to Pakistan;

(b) wheher any survey has been done to select a suitable site for the purpose;

(c) if so. the detail thereof; and

(d) if not, the reasons for not strengthening the Naval installations along the long Gujarat coast?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) The Navy already has a Naval Base INS Dwarka at Okha in Gujarat. In addition, a Naval Officer-in-charge (Gujarat) of the rank of Commodore is stationed at Porbandar. Therefore, presently there is no requirement of an additional Naval base.

(d) The existing infrastructure of the Navy on the Gujarat coast is presently adequate to meet the security requirements of the area

रक्षा परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि

1890. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक रक्षा संबंधी परियोजनाओं के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान तीनों सेवाओं के लिये उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वित्तीय आबंटन में कोई असमानता पाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थगित करना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान रक्षा से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिये पूंजी के तहत 30,33.87 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था । सेनावार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रु० में)

सेना	9,486.72
नौसेना	7,559.57
वायुसेना	13,277.58
कुल :	30,323.87

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में छावनी बोर्ड

1891. **श्री ओंकार सिंह लखावत :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने छावनी बोर्ड कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या अजमेर में छावनी बोर्ड का एक वार्ड पलटन बाजार में है, यदि हां, तो उस क्षेत्र में पानी, सफाई, स्वास्थ्य तथा नागरिक सुविधाओं का व्यवस्था संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) अजमेर के छावनी क्षेत्र में नागरिकों द्वारा निर्माण संबंधी पूर्व अनुमति लिये बिना दशकों पहले बनाये गये मकानों को विनियमित करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है?

रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज : (क) राजस्थान में अजमेर और नसीराबाद में दो छावनी बोर्ड कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जी, हां । अजमेर छावनी के पलटन बाजार वार्ड में प्रतिदिन एक लाख लीटर पानी प्राप्त होता है और उसका 16 नलों तथा 180 निजी कनेक्शनों के माध्यम से एक घंटे के लिये वितरण किया जाता है । सोडियम लैम्प/ट्यूब लाइट लगे 57 खंभों के माध्यम से सड़कों पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है । पक्की सड़कों, सार्वजनिक शौचालयों, टाइलयुक्त नालियों की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर सीमेंट के कड़ाघरों का निर्माण करवाया गया है । इस क्षेत्र में छावनी बोर्ड एक औषधालय भी चला रहा है ।

(ग) प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के अनुसार कार्रवाई की जाती है और छावनी बोर्ड द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 178 से 185 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार समुचित निर्णय लिया जाता है ।

System of integrated direction and command

1892. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to bring about a change in the decision-making process of the armed forces by introducing the system of integrated direction and command; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) The process of refining and improving the higher command and organisation and structure in the armed forces is a matter that engages the attention of the Government including senior officials of the armed forces on a continuing basis with a view to evolving a structure that is suited to the specific requirements of India. This has to take into account the existing command organisation and structure, the historical experience of the country and the specific requirements of contemporary forms of warfare. Recently Government has set up a National Security Council of which the strategic Policy Group, which inclcudes the Chiefs of staff of three Services, is a constituent unit. One of the prio rity tasks of this body would be to undertake a strategic defence review. The Defence Minister's Committee which meets every month and Raksha Mantri's weekly meeting are also forums where such matter are discussed from time to time.